>

Title: Need to impress upon State Government to recruit employees on regular and permanent basis instead of temporary and adhoc basis.

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): वर्तमान में मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में चल रही संविदा एवं तदर्थ आधार पर नियुक्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं सरकारी प्रभुत्व वाली कंपनियों में कर्मचारियों की अत्यंत कमी है तथा इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा पढ़े-लिखे एवं योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा एवं तदर्थ आधार पर की जा रही है एवं कई जगह तो यह देखने में आया है कि इनकी नियुक्ति कांट्रेक्ट बेस पर ठेकेदार के माध्यम से अल्पकाल के लिए की जाती है। इन कर्मचारियों की तदर्थ एवं संविदा आधार पर नियुक्ति होने के कारण इनकी सरकार एवं जनता के प्रति कोई जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व भी नहीं होता है तथा वे सरकारी गोपनीयता के नियम के प्रति भी बाध्य नहीं होते हैं।

इनको इनकी सेवा के लिए जो वेतन एवं प्रतिफल दिया जाता है वो भी तय मानकों से बहुत कम होता है। इस प्रकार उनका शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से शोषण भी होता है।

मेरा अनुरोध है कि मध्य प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाए कि संविदा एवं तदर्थ आधार पर नियुक्ति को बंद किया जाए एवं सरकारी माध्यम से नियमित आधार पर कर्मचारी नियुक्त किए जाए जिससे कि देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके।